



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53471

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 284 वर्ष 2026

राकेश कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कमलेंद्र कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. मौर्य और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान संक्षिप्त धारक श्री संदीप सिंह को सुना।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को परमादेश की प्रकृति में एक निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है कि वे कुरपुरा, परगना और तहसील- बिधुना, जिले- औरैया में स्थित 0.1454 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ प्लॉट संख्या 14/10/2 में आने वाली भूमि के अलावा याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को पहले इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि आरोप थे कि राजस्व अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की भूमिधारी भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए याचिकाकर्ता की चारदीवारी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से अवैध रूप से आगे बढ़ाया है।

4. इस मामले में एक व्यक्तिगत हलफनामा सत्यवीर पाल, तहसील बिधुना, जिला- औरैया के लेखपाल द्वारा दायर किया गया है। हलफनामे के अनुसार, प्लॉट नंबर 14 एक बहुत बड़ी संख्या है जिसका कुल क्षेत्रफल 12.7480 हेक्टेयर है, जिसमें विभिन्न पट्टेदार धारकों की भूमि को अलग-अलग खाता संख्या के रूप में अलग किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि तहसील को 2.23 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ खाता संख्या 185 के रूप में भी दर्ज किया गया है। विचाराधीन भूमि की विभिन्न खतौनियों को रिकॉर्ड पर लाया गया है, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता को अन्य सह-कार्यकाल धारकों के साथ 0.1454 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ प्लॉट नंबर 14 के संबंध में भी दर्ज किया गया है। राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान संक्षिप्त धारक श्री संदीप सिंह द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का बिक्री विलेख जिसके माध्यम से उसने मूल कार्यकाल धारक से भूमि खरीदी है, भूमि की पहचान करने के लिए कोई सीमा नहीं दिखाती है क्योंकि मूल कार्यकाल धारक की भूमि का केवल दो-तिहाई हिस्सा उसे बेच दिया गया था, जिसका अर्थ है कि मूल कार्यकाल धारकों को सह-कार्यकाल धारकों के रूप में दर्ज किया जाना जारी रहा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस प्रकार, यह तर्क देने की मांग की जाती है कि यदि याचिकाकर्ता सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है, तो सरकार को बाउंड्री वॉल गिराने की स्वतंत्रता है, यदि कोई हो। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत संयुक्त कार्यवाही द्वारा अपनी भूमि को मापना चाहिए, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

5. इसके विपरीत, उपरोक्त प्रस्तुतियों को पूरा करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विध्वंस का कोई भी अभ्यास वैध अधिकार के अभाव में बुरा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी तहसीलदार या लेखपाल को संबंधित याचिकाकर्ता/कार्यकाल धारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता की भूमि को मौके पर ही पहचाना नहीं जा सकता है क्योंकि जिस बिक्री विलेख पर भरोसा किया गया है, वह भूमि को एक अलग भूमि के रूप में मजबूत करने वाली किसी भी सीमा को दर्ज नहीं करता है।

7. इसलिए, परिस्थितियों में, ऐसे प्रत्येक कार्यकाल धारक जो एक रिकॉर्ड किए गए कार्यकाल धारक से भूमि खरीदता है, उसे पहली बार में अपनी भूमि का सीमांकन करवाना चाहिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब केवल भूमि का एक टुकड़ा खरीदा जाता है और मूल कार्यकाल धारक शेष भूमि को बरकरार रखता है। वर्तमान मामले में, दो-तिहाई भूमि खरीदी गई थी और एक तिहाई भूमि मूल कार्यकाल धारक द्वारा रखी गई थी, जिसे बाद में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकारी बनाया गया था। न तो वारिस, न ही सह-कार्यकाल धारक हमारे सामने हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तदनुसार, हम याचिकाकर्ता को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही करके अपनी भूमि को मापने और पहचानने के लिए अन्य सह-कार्यकाल धारकों को प्रेरित करके जो उसके विक्रेताओं के उत्तराधिकारी हैं और यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो आवेदन पर विचार किया जाएगा और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर सभी संबंधित और इच्छुक पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद उसका निपटान किया जाएगा।

9. हालांकि, हम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सावधानी का एक नोट दर्ज करते हैं कि किसी भी जबरदस्ती की कार्यवाई के मामलों में, प्रशासनिक अधिकारियों को एक ही समय में उस पक्ष को सुनने की आवश्यकता होती है जो प्रभावित होने जा रहा है। भविष्य में राजस्व अधिकारी और नागरिक पुलिस प्रशासन इसका ध्यान रखेंगे।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

मार्च 20, 2026

शिव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।